आयुक्त ने डीईओ से बुलाई मृत, संक्रमित शिक्षकों की जानकारी

एक्सग्रेशिया की राशि का तुरंत किया जाए भुगतान

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना से भोपाल जिले में कोरोना से मृत एवं संक्रमित हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। डीईओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से तत्काल यह सूची भेजने को कहा है। मंगलवार को डीईओ ऑफिस में यह सूची तैयार की गई। सक्सेना ने बताया कि विमर्श पोर्टल पर यह सूची अपलोड की जाएगी। एक्सग्रेशिया तत्काल देने के आदेश विभाग द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि मृत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया की राशि का तुरंत भुगतान किया जाए।

10 दिन में 10 शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत

शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना ने बताया कि भोपाल जिले में पिछले 10 दिन में आयुक्त दफ्तर, राज्य शिक्षा केंद्र और विभिन्न स्कूलों के 10 से ज्यादा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। जिले में 100 से ज्यादा कर्मचारी एवं शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी संक्रमित भी हो रहे हैं।

स्थाई कर्मियों के परिजनों को मिले अनुकंपा नियुक्ति

इधर, निगम मंडलों से जुड़े कर्मचारी संघों ने शासन से मांग की है कि कोरोनाकाल में मृत स्थाई कर्मियों के परिजनों को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। निगम मंडल महासंघ, हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, हाउसिंग कारपोरेशन कर्मचारी संघ नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारी संघ, राज्य परिवहन निगम कर्मचारी संघ सहित अन्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जीएडी को संयुक्त पत्र भेजा है। इन संगठनों के अजय श्रीवास्तव, अनिल बाजपेई, गजेंद्र कोठारी, बलवंत सिंह रघुवंशी, श्यामसुंदर शर्मा, मेघराज यादव समेत कई पदाधिकारियों ने मांग की है।

Badri Gautam

नई गाइडलाइन • 30 अप्रैल तक गांव-गली, मोहल्ला सभी में जनता कर्फ्यू

सरकारी और निजी कार्यालयों में अब सिर्फ 10% कर्मचारियों की अनुमति

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल

मो.नं. 9425078939

प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में अब 10 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। यह नियम निजी दफ्तरों, आईटी और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है।

गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए इसके अनुपालन की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी है। आदेश में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को आवश्यक सेवाएं माना गया है।

जानें नई गाइडलाइन

ऑटो-ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर व 2 पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति।

धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स व मनोरंजन गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी।

Badri Gautam

विवाह में सीमित लोगों की अनुमति

जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रदेश में सीमित संख्या में विवाह की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही बाबा रामदेव और श्रीश्री रविशंकर की टीम मप्र में अपना योगदान देंगी।

सब्जी मंडियां भी कर्फ्यू के दायरे में

प्रदेश की सभी सब्जी मंडियों को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटी-छोटी मंडियों की अनुमति दी गई है, ताकि एक स्थान पर ज्यादा भीड़ न हो।

केंद्र ने कहा- अगले तीन हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बताया कि अगले तीन सप्ताह कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तीन हफ्तों के लिए रणनीति बनाएं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत की दैनिक मामलों की संख्या जनवरी की अपेक्षा 10 गुना से अधिक बढ़ गई है।

फैसला | केंद्र सरकार ने 52 लाख कर्मचारियों को दिया तोहफा

एक जुलाई से 28 फीसदी डीए होगा बहाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम के बाद देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभ को बहाल करने जा रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज के मुताबिक, जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है। डीए बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है।

Badri Gautam

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

जैसा कि केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से सभी तीन लंबित डीए किस्तों को दिए जाने की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। डीए बढ़ने से उसी अनुपात में डीआर में भी बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में इजाफा होने से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का डीआर भी बहाल कर दिया जाएगा।

पीएफ और ग्रेच्युटी में होगा बदलाव

संभावित डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर्मचारी के मासिक पीएफ, ग्रेच्युटी योगदान पर भी असर डालेगी। सीजीएस के पीएफ व ग्रेच्युटी के योगदान की गणना मूल वेतन प्लस डीए के आधार पर की जाती है। 1 जुलाई 2021 से डीए बढ़ने वाला है, एक कर्मचारी का मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी का योगदान में भी इसका असर दिखेगा। इसका मतलब है कि पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट-ओरिएंटेड फंड्स में ज्यादा पैसा जमा होगा।

कोरोना के कारण यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में प्रस्तावित यूजीसी-नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। स्थिति सामान्य होने पर ही परीक्षा की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकने मंगलवार को ट्वीट कर नेट टलने की जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा बाद में होगी। छात्रों को परीक्षा के लिए कम से कम पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा। 81 विषयों के लिए होने वाली यह परीक्षा दो मई से 17 मई के बीच देश भर में होनी थी। वैसे तो यह परीक्षा दिसंबर में ही होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे मई में कराने का फैसला लिया गया था। इससे पहले सरकार ने जेईई मेंस की अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं को भी टालने का फैसला लिया था।

आइसीएसई बोर्ड ने भी दसवीं की परीक्षा रद की

इस बीच छात्रों के दबाव को देखते हुए आइसीएसई ने दसवी बोर्ड की परीक्षा रद कर दी है। यानी अब दसवीं की परीक्षा नही होगी और छात्र आंतरिक आकलन के आधार पर पास घोषित किए जाएंगे। इससे पहले आइसीएसई ने दसवी बोर्ड के छात्रों को दो विकल्प दिए थे। जिसमें वह परीक्षा देना चाहते है या फिर नही। यदि परीक्षा देना चाहते हैं तो उनकी परीक्षाएं बारहवी की बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही कराने का फैसला लिया गया था। साथ ही जो नही देना चाहते उन्हें आंतरिक आकलन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।

Badri Gautam

अब 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा स्थगित

हरिभूमि न्यूज ⏭भोपाल

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति के लिए 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी।

राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक ओएल मंडलोई ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 15 अप्रैल थी, जिसे 15 मई 2021 तक बढ़ाया गया है। इच्छुक छात्र एमपी-ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

9 से 12वीं तक मिलती हैं छात्रवृत्ति

बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की थी। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से बारहवीं तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा आठवीं में अध्यनरत नियमित छात्र, जिन्होंने कक्षा सातवीं में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

Badri Gautam

आईसीएसई बोर्ड ने लिया फैसला

10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की परीक्षा पर फैसला जून में

Badri Gautam

- 12वीं की परीक्षाएं पहले ही स्थगित

नई दिल्ली। कोरोना के कारण अब सीआईएससीई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं कैंसल कर दी हैं। पहले बोर्ड के नोटिफिकेशन में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा वैकल्पिक रखी गई थी। कक्षा 10वीं के जो छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, बोर्ड उनके लिए विशेष मूल्यांकन पद्धति से परिणाम तैयार करेगा। वहीं, जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वे कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

कोरोना • प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी

प्रदेश: 30 तक कोरोना कर्फ्यू

भास्कर न्यूज . भोपाल| प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इस बार लोगों को घरों से किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। गांवों में टोटल कर्फ्यू सख्ती से रखा जाएगा।

कलेक्टर-कमिश्नर से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- जनता ने ही कहा है- सख्ती होना चाहिए। गृह विभाग ने भी नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक जरूरी सेवाओं को छोड़कर केंद्र व राज्य के बाकी सरकारी दफ्तर सिर्फ 10% स्टाफ के साथ खुलेंगे। आईटी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ, यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी दफ्तर भी 10% क्षमता से खुलेंगे। हालांकि सवारी वाहनों में कुछ छूट दी गई है। ऑटो रिक्शा में दो, कारों में ड्राइवर, दो पैसेंजर की अनुमति दी गई है। मास्क जरूरी होगा। बाकी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। व्यापारियों से कहा गया है कि वे बड़ी सब्जी मंडियों के बजाय छोटे-छोटे बाजार अलग-अलग क्षेत्रों में खोलें।

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा...

▪ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे। ▪ जबलपुर, टीकमगढ़ और इंदौर की स्थिति की विशेष समीक्षा में बताया गया कि इंदौर में पिछले एक सप्ताह से संक्रमण की दर 20 प्रतिशत के आसपास ही है। ▪ पॉजिटिविटी दर के आधार पर कलेक्टरों की भी रैंकिंग होगी। ▪ कोरोना संक्रमण से लड़ने में श्री श्री रविशंकर व उनकी टीम भी मप्र की मदद करेगी। वे आयुर्वेदिक उपचार के साथ खानपान और अवसाद-बैचेन लोगों को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करेगी। यह सब काम फोन से होगा। ▪ जबलपुर एवं छिंदवाड़ा जिले में कोरोना नियंत्रण, बचाव एवं उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

Badri Gautam

तीसरे दिन 12 हजार से ज्यादा संक्रमित, 10 दिन में 1 लाख केस

प्रदेश में बीते दस दिन में एक लाख नए संक्रमित मिल चुके हैं। बीते तीन दिन से 12 हजार से ज्यादा केस मिल रहे हैं। मंगलवार को 51385 सैंपल की जांच में 12727 नए केस मिले। एक्टिव केस 78271 हो चुके हैं। सबसे कम एक्टिव केस 153 खंडवा में हैं। भोपाल में 9037 एक्टिव केस हैं।

पॉजिटिविटी रेट 0.5 प्रतिशत घटा

▪ सोमवार को संक्रमण दर 25.3% थी, जो मंगलवार को 24.8% हुई है। छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर में भी संक्रमण कम हुआ है। ▪ दिल्ली-मुंबई से लौट रहे मजदूरों के लिए बसें तैनात हैं। इंदौर-उज्जैन संभाग का काम डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर देखेंगी। जो भी बस आएगी, उसे खालीकर 2-3 बसों में बांटा जाएगा। मजदूरों को गांव के पंचायत भवन, स्कूलों में आइसोलेट करेंगे।

समाजसेवियों ने दी कोरोना जांच किट

अध्यापक मोर्चा ने कोविड सेंटरों को दिए उपकरण

Badri Gautam

नरसिंहपुर. कोरोना महामारी से लड़ाई में हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। अध्यापक संयुक्त मोर्चा ने कोविड मरीजों के लिए जरूरी स्वास्थ्य उपकरण भेंट किये हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड की कमी होने की वजह से कोविड केयर सेंटरों को पुनः शुरू किया गया है। इन कोविड केयर सेंटरों में भर्ती होने वाले मरीजों के उपचार व आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिले के अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा राशि का संग्रह किया जा रहा है । जिनमें 3 वाटर डिस्पेंसर नरसिंहपुर एवं एक,एक वाटर डिस्पेंसर मशीनें गोटेगांव, करेली, तेन्दूखेड़ा, चीचली तथा गाडरवारा में बनाये गए कोविड केयर सेंटरों में प्रदान की गई हैं। इसके अलावा अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रत्येक कोविड केयर सेंटर के लिए 16 वाटर बोतलें, 16 ब्लड प्रेशर मॉनीटर, 16 पल्स ऑक्सीमीटर सामग्री और क्रय की जा रही है जिसे जल्द कोविड सेंटरों को प्रदाय किया जाएगा। ऑक्सीजन जनरेटर भी क्रय किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग व पुलिसकर्मियों के समान कार्य कर रहे शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर्स मानें

प्रदेश के शिक्षा मंत्री से शिक्षकों का आग्रह, दिवंगत होने पर कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

प्रदेशभर में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण सैकड़ों अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी दिवंगत हो गए हैं। जिले में लगभग 50 कर्मचारी, शिक्षकों की मृत्यु हो गई है। 120 से अधिक शिक्षक कोरोना से संक्रमित होकर इलाज करवा रहे हैं।

प्रांतीय शिक्षक संघ और मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री ईश्वर सिंह परमार को पत्र भेजकर यह आग्रह किया है। कैलाश बारोड़ व नरेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया उनसे आग्रह किया है कि प्रदेश भर में शिक्षकों से सीधे-सीधे कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के काम लिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी, क्वारेंटाइन क्षेत्र की निगरानी, सर्वे कार्य, चेक पोस्ट, कंट्रोल रूम यानी स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों के काम के समान ही शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। शिक्षकों को फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं माना जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि शिक्षकों के साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है। हम शिक्षक किसी प्रकार की ड्यूटी करने से मना नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में हम भी शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। कई साथी हमारे दिवंगत हो गए हैं। इससे भय का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी फ्रंटलाइन कर्मचारी शिक्षकों को नही माना जा रहा है

Badri Gautam

कर्मचारी संघ ने यह प्रमुख मांगें भी रखीं

- दिवंगत अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी को कोरोना योद्धा मानकर 50 लाख रुपए का बीमा धन व अन्य सुविधाएं प्रदान करें।
- दिवंगत शिक्षक के परिवार के सदस्य को बिना किसी शर्त के अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें।
- जिलास्तर पर दिवंगत कर्मचारी के समस्त आर्थिक प्रकरणों का निराकरण करें।
- बिना स्वास्थ्य किट के किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई जाए।
- संक्रमित कर्मचारी का उत्तम इलाज किसी निजी अस्पताल में करवाएं, खर्च का वाहन शासन-प्रशासन करें।
- ड्यूटी पर भेजने से पहले प्रत्येक कर्मचारी का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
- किसी कारण से पर्याप्त सुविधा व सुरक्षा शिक्षकों को प्रदान नहीं की जा सकती है, तो उन्हें कोरोना की डयूटी से मुक्त रखा जाए।
- अध्यापक संवर्ग को तो न कोई पेंशन मिलती है न जीपीएफ और न ही सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं, वे दिलवाएं।

135 बीएड कॉलेज नहीं दे सके जानकारी, एडमिशन होंगे शून्य

कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने बढ़ाई आवेदन की तिथि

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीएड कॉलेजों को पर्याप्त समय देने के बाद भी पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की गई। इसके चलते अभी की स्थिति में प्रदेश के 135 काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और उनमें एडमिशन शून्य रहेगा।

प्रदेश के बीएड के 647 कॉलेजों ने एनसीटीई से मान्यता ली है, लेकिन सत्र 2021-22 में प्रवेश कराने के लिए अभी तक 512 कॉलेजों ने पोर्टल पर जानकारी अपलोड की है। इसके चलते 135 कॉलेज काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और उनमें जीरो प्रवेश रहेगा। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। इसलिए विभाग ने अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय

Badri Gautam

लिया है। इसके चलते विभाग ने प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश कराने संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। इसी के चलते विभाग ने कॉलेजों को सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए उनसे 15 अप्रैल तक सभी जानकारी पोर्टल के जरिए भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रदेश 512 कॉलेजों ने भागीदारी की है। अभी भी 135 कॉलेजों ने प्रवेश देने के लिए कोई संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को देख विभाग ने 25 अप्रैल तक लॉगिन पासवर्ड से उन्हें दस्तावेज जमा करने का एक मौका और दिया है।

संबद्धता के बाद मिलेगी एनसीटीई कोर्स की मान्यता

अभी तक विभाग कॉलेजों के समस्त प्रकार के दस्तावेजों को देखने के लिए भौतिक तौर पर दस्तावेजों का परीक्षण कमेटी द्वारा कराता था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया है। इसके चलते पोर्टल पर दी गई जानकारी को विवि पहले संबद्धता देते हुए ओके करेगा। इसके बाद विभाग कॉलेजों के एनसीटीई से कोर्स की मान्यता और प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा फीस निर्धारित कराने के पत्र का परीक्षण करेगा। इसके बाद उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउसंलिंग में प्रदेश के 516 बीएड कालेज शामिल हुए थे। विभाग ने उनकी 51 हजार 700 सीटों में प्रवेश के लिए दिसंबर तक काउंसलिंग हुई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग हर साल राज्यपाल को नहीं भेज रहा प्रतिवेदन

प्रदेश में एसटी, एससी वर्ग के कितनों को मिली नौकरी, राजभवन को नहीं मिली चार साल से जानकारी, अब सचेत हुआ जीएडी

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

सरकारी विभागों में आरक्षण नियम का कितना पालन हो रहा है। एक साल में कितने आरक्षितों को सरकारी नौकरी दी गई और कितने पद खाली हैं। इस संबंध में हर साल राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजने का नियम है, लेकिन वर्ष 2016 से राज्यपाल को ये प्रतिवेदन भेजा ही नहीं गया। अब कहीं जीएडी सचेत हुआ और बीते दो साल का प्रतिवेदन तैयार करने विभागों से रिपोर्ट तलब की है।

मप्र लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-19 के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पर रखे जाने

वाले लोगों का प्रतिवेदन हर साल राज्यपाल को भेजे जाने का नियम है, लेकिन ये प्रतिवेदन राज्यपाल को बीते चार साल से नहीं भेजा गया है। वर्ष 2016-17 के प्रतिवेदन में प्रदेश के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्ग के 23 हजार पद खाली होने का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसके बाद से कितने विभागों में आरक्षित वर्ग के पद भरे गए हैं और कितने पद खाली है, इस संबंध में प्रतिवेदन भेजा ही नहीं गया। खासकर वर्ष 2016 में मप्र हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण नियमों के तहत दी गई पदोन्नति पर रोक लगा देने के बाद से सालाना प्रतिवदेन तैयार करने जीएडी के अफसरों रुचि नहीं दिखाई। अब कही जाकर विभागों को परिपत्र भेजकर वर्ष 2019 एवं 2020 की रिपोर्ट मांगी गई है।

Badri Gautam

सचिव को जानकारी नहीं

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्रीनिवास शर्मा से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। विभाग में उप सचिव देखते होंगे। जब विभाग की उपसचिव दिशा नागवंशी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दफ्तर में कर्मचारियों की उपस्थिति 10 प्रतिशत हो गई है, इसलिए आरक्षण प्रकोष्ठ देखने वाला कर्मचारी नहीं है। दफ्तर पूरा खुलने पर ही बता सकेंगे।

किस वर्ग को कितना मिल रहा आरक्षण

वर्ग	आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति	16
अनुसूचित जनजाति	20
अन्य पिछड़ा वर्ग	27
आर्थिक रूप से कमजोर	10
निःशक्तजनों के लिए	06

एजुकेशन अपडेट्स

आईआईटी इंदौर के नए एमटेक प्रोग्राम्स के रजिस्ट्रेशन 15 जून तक

सिटी रिपोर्टर | आईआईटी इंदौर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग जैसे नए एमटेक प्रोग्राम्स और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस इंजीनियरिंग जैसे एमएस (रिसर्च) प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स www.iiti.ac.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून है। एमटेक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी दो वर्ष का कोर्स है। इसके लिए कैन्डिडेट्स के पास चार या पांच साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेन्टेशन एंड कंट्रोल, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ गेट स्कोर कार्ड होना जरूरी है।

Badri Gautam

विद्यार्थियों का डाटा नहीं किया अपलोड

भोपाल(नप्र)। स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग हर साल सरकारी कालेजों से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की जानकारी बुलाता है। मगर सत्र 2019–20 में पास विद्यार्थियों का डाटा 100 कॉलेजों ने ही अपलोड किया है। कॉलेजों की लापरवाही से विभाग को यह पता लगाने में परेशानी हो रही है कि कितने विद्यार्थियों की नौकरी लगी और कितनों ने खुद का व्यवसाय शुरू किया।

Badri Gautam

अगले सत्र से आइआइटी इंदौर में चार नए कोर्स

इंदौर। जुलाई 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी इंदौर) में चार नए पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। दो वर्षीय एमटेक और एमएस कोर्स में सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश दिया जाएगा। आनलाइन पोर्टल के जरिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान जल्द ही तारीख घोषित करेगा। संस्थान में आठ यूजी और 29 पीजी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

अगले सत्र में एमटेक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलाजी, एमटेक इन अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान, एमएस इन अंतरिक्ष विज्ञान और एमएस इन मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान ये चार नए कोर्स शुरू होंगे। शिक्षकों का कहना है कि अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में बुनियादी अवधारणाओं और स्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। देश में अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्थान में शोध-आधारित शिक्षण में लगे हुए लगभग 155 संकाय सदस्यों द्वारा आठ अंडर ग्रेजुएट (पांच मेजर और तीन माइनर) और 29 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

Badri Gautam

जीईसी के 35 शिक्षकों का 6 महीने और बढ़ा कार्यकाल

अब 30 सितम्बर तक छात्रों को पढ़ा सकेंगे

जागरण, रीवा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के 35 शिक्षकों का अनुबंध 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये शिक्षक 30 सितम्बर 2021 तक महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर सकेंगे। हालांकि लॉकडाउन के चलते इन शिक्षकों का बहुत लाभ महाविद्यालय को मिलना मुश्किल है। न तो भौतिक कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय करा पायेगा और न ही एनबीए से मूल्यांकन इस अवधि में हो सकेगा। फिर भी उक्त 35 शिक्षकों का हित तो आगामी 6 माह के लिए हो गया। अब 6 माह के बीच यदि इन शिक्षकों को राज्य सरकार अपने अधीन नहीं कर पाती तो उन्हें महाविद्यालय से बाहर होना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कार्यावधि बढ़ाते समय यह स्पष्ट कर दिया है।

गौरतलब है कि वर्ल्ड बैंक ने अनुबंध के तहत महाविद्यालय में तीन साल पहले 35 शिक्षकों को भेजा था, जिनका कार्यकाल विगत 30 सितम्बर 2020 को पूरा हो गया था। फिर सितम्बर माह में इन शिक्षकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया, जिसके समाप्त होने तक अप्रैल माह के पहले सप्ताह में इन शिक्षकों की कार्यावधि बढ़ा दी गई।

नहीं बना रोस्टर

बता दें कि टेक्विप-3 परियोजना के तहत एनपीआईयू द्वारा इन शिक्षकों को अनुबंधित किया गया। चूंकि उक्त नियुक्ति को लेकर रोस्टर नहीं बना, इसलिए राज्य शासन ने भी इन शिक्षकों को नियमित करने अब तक गम्भीरता से विचार नहीं किया। जबकि उक्त शिक्षक महाविद्यालय में निरंतर सेवा देना चाहते हैं परंतु अनुबंध के अनुसार उन्हें महाविद्यालय में अब केवल 6 माह और पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।

एनबीए के मूल्यांकन पर अब भी संशय

इन 35 अनुबंधित शिक्षकों के होने पर 55 शिक्षकों की मौजूदगी दर्शायी जा सकती है। जिससे महाविद्यालय की एनबीए स्कोरिंग में सुधार सम्भव होगा परंतु महाविद्यालय न तो इन शिक्षकों के रहते एनबीए से मूल्यांकन करवा पाया और न अब अगले 6 महीने महाविद्यालय मूल्यांकन कराने की स्थिति में है। चूंकि कोरोनाकाल में कोई भी एनबीए मेम्बर यहां मूल्यांकन हेतु आने सहमति नहीं देगा, इसी कारण विगत 27 मार्च 2020 का मूल्यांकन भी टल गया था। अब आगामी 6 महीने भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। यानि महाविद्यालय को इन शिक्षकों से फिलहाल बहुत लाभ मिलना कठिन है।

Badri Gautam

बीयू के जिम्मेदार नहीं एकमत 24 घंटे में 3 बार बदला आदेश

50 प्रतिशत स्टाफ के आदेश का विरोध

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) भी कोरोना संक्रमण से बच नहीं सका है। यहां कई कर्मचारी व अधिकारी पॉजीटिव चुके हैं। ऐसे में बीयू प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में कई बदलाव कर रहा है, लेकिन यह बदलाव भी बीयू प्रशासन के जिम्मेदारों के एक मत नहीं होने से उलझ रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला इन दिनों सामने आया है, जब एक ही आदेश को 24 घंटे में तीन बार बदला गया है। सोमवार को बीयू रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी ने पहले 26 अप्रैल तक सभी विभागों को बंद करने का आदेश किया था, जिसमें अत्यावश्यक सेवाएं चालू रखने का उल्लेख था। लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही कुलपति प्रो. आरजे राव के निर्देश पर दूसरा आदेश जारी हुए जिसमें 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने को कहा गया। वहीं इस गलत आदेश का कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर एक बार फिर से पूर्व आदेश को यथावत कर दिया गया है।

हालांकि मामले में बीयू रिजस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी का कहना है कि कोरोना की स्थिति राजधानी में ज्यादा खराब है, इसलिए कलेक्टर के आदेश के परिपालन में 26 अप्रैल तक कार्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश प्रदेश भर के लिए हैं, जबकि कलेक्टर के आदेश परिस्थितियों के अनुसार जारी हुए हैं।

Badri Gautam

इस बार भी मेरिट आधार पर होंगे प्रवेश!

सीईटी पर संकट, मई पहले सप्ताह में विवि ले सकता है फैसला

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के कारण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कामन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी) पर संकट मंडरा रहा है। प्रवेश परीक्षा की बजाय यूटीडी में इस साल भी मेरिट आधार पर दाखिला देने की संभावना बनती दिख रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, मगर अधिकारियों ने परीक्षा नहीं करवाने की सलाह दी है। मामले में अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जा सकता है। संभवत: मई पहले सप्ताह में विभागाध्यक्षों की बैठक होगी।

तक्षशिला परिसर स्थित विश्वविद्यालय के लगभग 12 विभागों के 36 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीईटी करवाई जाती है, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से मेरिट आधार पर विद्यार्थियों को 2300 से ज्यादा सीटों पर दाखिला दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल परीक्षा आयोजित करवाने की तैयारी की है। आनलाइन परीक्षा के लिए एक एजेंसी से बातचीत भी कर ली। मगर मार्च से कोरोना की दूसरी

देवी अहिल्या विवि। ●फाइल फोटो

लहर आने के बाद अब विश्वविद्यालय फिर एक बार मेरिट आधार पर विद्यार्थियों को एडमिशन दे सकता है। प्रवेश समिति भी इसके लिए राजी है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विभागाध्यक्षों ने एमपी बोर्ड-सीबीएसई के 12वीं कक्षा और यूजी फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद काउंसिलिंग शुरू करने का मन बनाया है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय को मई-जून तक इंतजार करना पड़ सकता है। कुलपति डा. रेणु जैन का कहना है कि सीईटी के लिए अभी थोड़ा वक्त है। मेरिट और प्रवेश परीक्षा को लेकर फैसला लेना है। इसके लिए विभागाध्यक्षों से राय लेंगे। जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी।

कम होगी बाहरी विद्यार्थियों की संख्या

आइएमएस, आइआइपीएस, ईएमआरसी, कामर्स, ला, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स, इकोनामिक्स सहित अन्य विभागों के कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। मेरिट आधार पर प्रवेश को लेकर कुछ विभागाध्यक्षों ने संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होगा तो इस साल भी विश्वविद्यालय में बाहरी राज्यों व शहरों के विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी। विश्वविद्यालय में इंदौर और आसपास के छात्र-छात्राएं ही दाखिला लेंगे। उधर प्लेसमेंट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां मेरिट की बजाय प्रवेश परीक्षा से चयनित विद्यार्थियों को नौकरियां देने की अधिक इच्छुक रहती हैं।

Badri Gautam

हिंदी विवि ने रोस्टर जारी कर बुलाई आपत्तियां

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मुगालिया कोट स्थित अटल विहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के 18 पदों पर सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए भर्तियां निकाली है।

विवि के कुलसचिव ने आदेश जारी कर विभिन्न पदों पर रोस्टर जारी किया है। इनमें आरक्षित व अनारक्षित पदों के लिए जारी किया है। रजिस्ट्रार ने भर्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार ने आपत्ति मांगी है। आपत्तियों के निराकरण के बाद विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आदेश में लिखा है कि विवि द्वारा जारी रोस्टर के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो लिखित में विवि के कुलसचिव के नाम पर डाक से या विवि के वेबसाइट पर 21 दिन के अंदर आवेदन भेजे। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपत्ति संबंधी आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। विवि ने अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, इतिहास, कृषि विज्ञान, गणित, पत्रकारिता एवं संचार, प्रबंधन एवं वाणिज्य, प्राणिशास्त्र, भारतीय दर्शन एवं ज्ञान परंपरा, भौतिकशास्त्र, योग एवं मानव चेतना, रसायनशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन, वनस्पति विज्ञान, विधि, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य, संगणक, हिंदी भाषा एवं अनुवाद विषय के एक-एक पद पर रिक्तियां निकाली गई है।

अध्ययन केंद्र के लिए 20 मई तक आवेदन

विवि ने आदेश जारी किया है कि मप्र के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क 20 हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ विवि के ईमेल पर या डाक से जमा कर सकते हैं।

Badri Gautam

अस्पतालों की मॉनिटरिंग करने नहीं पहुंचे

28 शिक्षक, अफसर और कर्मचारी अब होंगे सस्पेंड

कलेक्टर ने दिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पतालों में व्यवस्था को सुचारू बनाने और लगातार मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एडीएम ने कोविड -19 तहत अस्पतालों में निगरानी के लिए कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। निर्देश के बाद भी ये अधिकारी व कर्मचारी कार्य स्थल पर नही पहुंचे। कलेक्टर ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

हरीश रूपाणी, सहायक ग्रेड -3, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रघुवीर सिंह राठौर, सहायक शिक्षक शासकीय बालक स्कूल स्टेशन क्षेत्र, आरपी गोयल, सहायक वर्ग -2 , अनुसंधान अधिकारी सिंचाई अनुसंधान जल संसाधन, हरीश कुमार गिदवानी, सहायक वर्ग -2, अनुसंधान अधिकारी जल संसाधन, संजय कुमार टांक, सहायक वर्ग -3, अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग, अवधेश श्रीवास्तव, सहायक शिक्षक, उ.मा.वि. स्टेशन क्षेत्र शामिल हैं। इनके अलावा बाला प्रसादओर कन्हाइलाल अनुसंधान अधिकारी जल सिंचाई अनुसंधान जल संसाधन, विजय प्रकाश मेहरा, सहायक शिक्षक, उ.मा. वि. स्टेशन क्षेत्र, फरहान अली खान, सहायक वर्ग -3, अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग, चन्द्रशेखर, सहायक वर्ग -3, अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग, राजन सोनी, सहायक ग्रेड -3, अनुसंधान एवं विस्तार पूल, नरेन्द्र कुमार चन्द्रावत सहायक शिक्षक, उ.मा.वि. स्टेशन क्षेत्र, सुनील कुमार, सहायक शिक्षक, उ.मा.वि. बैरागढ़, संतोष कुमार बसोने सहायक शिक्षक, शासकीय उ.मा.वि. बैरागढ़, शेखर गुप्ता सहायक वर्ग -3, अनुसंधान एवं विस्तार पूल, अनिल कुमार तिवारी सहायक शिक्षक, शासकीय उ.मा. वि. बैरागढ़, रामलाल मिश्रा सहायक वर्ग -3, अनुसंधान एवं विस्तार पूल, लक्ष्मीनारायण उसरेठे सहायक शिक्षक, नवीन कन्या उ.मा.वि. तुलसीनगर, हेमंत जैन उपयंत्री , कार्यपालन यंत्री स.क .1 राजधानी परियोजना प्रशासन, कमलेश वर्मा सहा.ग्रेड-3 आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान, पीयूष भटनागर स.शि. नवीन क.उ. मा.वि. तुलसी नगर, मनोज श्रवण कार्यपालन यंत्री स.कं.1 रा.परियोजना प्रशासन, संजय ढोके स.ग्रेड - 3 उच्च शिक्षा संचालनालय, कौशलेन्द्र प्रताप स.शि. शा.उ.मा. वि, प्रेमकुमार श्रीवास्तव उपयंत्री, कार्यालय उप संचालक एवं कार्यपालन यंत्री विशिष्ट सेवा, मनोज व्यास सहायक शिक्षक नवीन उ.मा.वि अरेरा कॉलोनी, सतीश कुमार शामिल हैं।

Badri Gautam

हिंदी विवि : प्रोफेसरों की भर्ती का रोस्टर 8 साल बाद जारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विवि ने डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए रोस्टर जारी कर दिया है। रोस्टर में जनसाधारण से आपत्तियां तलब की हैं।

हिंदी विवि में आठ साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आठ सालों में नौ असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद बढ़े हैं। पहली बार 2013 में जारी विज्ञापन में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के नौ पदे थे।

इन विभागों में नियुक्तियां

अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास, कृषि विज्ञान, पत्रकारिता एवं संचार, प्रबंधन एवं वाणिज्य, भारतीय दर्शन एवं ज्ञान परंपरा, भौतिकी, योग एवं मानव चेतना, रसायन, वनस्पति, विधि, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य, संगणक, हिंदी भाषा एवं अनुवाद, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन तथा प्रणाी शास्त्र आदि।

Badri Gautam

बीयू : अब प्राइवेट कॉलेजों में नियुक्त प्रोफसरों व प्राचार्यों की होगी जांच

आठ जिलों के 480 में से सिर्फ दो दर्जन कॉलेजों ने भेजी जानकारी, 54 बोर्ड ऑफ स्टडी का गठन मुश्किल

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

बीयू द्वारा 54 बोर्ड ऑफ स्टडी का गठन किया जाना है। इसके लिए बीयू ने संबद्ध प्राइवेट कॉलेजों से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्यों की सूची मांगी थी। अंतिम तारीख बीतने तक केवल दो दर्जन कॉलेजों ने जानकारी भेजी है।

जिन कॉलेजों ने जानकारी नहीं भेजी, उन पर बीयू कार्रवाई तैयारी कर रहा है। कॉलेजों द्वारा

जानकारी नहीं देने के पीछे सैलरी और छात्रवृत्ति को लेकर गड़बड़झाला होना बताया जा रहा है।बीयू से संबद्ध आठ जिलों के 480 प्राइवेट कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्यों की भर्ती को लेकर बडे स्तर पर गड़बड़ी की गई है। यह बात बीयू की बोर्ड ऑफ स्टडी के गठन के दौरान सामने आई।

कॉलेजों की नौकरी छोड़ चुके प्राचार्य बोर्ड में मौजूद

बोर्ड ऑफ स्टडी में प्राइवेट कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसर व प्राचार्यों को मेंबर बनाया जाता है। कई प्रोफेसर निजी कॉलेजों से नौकरी छोड़ चुके हैं, तो वहीं कुछ प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन वे अभी भी बोर्ड ऑफ स्टडी में बने हुए हैं। प्राइवेट कॉलेज उनका नाम अभी तक चला रहे हैं, क्योंकि कोड 28 के तहत नियुक्ति कराने में उन्हें लाखों रुपए का वेतन देना पड़ेगा।

जांच कराई जाएगी

प्राइवेट कॉलेजों द्वारा प्रोफेसर और प्राचार्य की नियुक्ति के नाम पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। कालेजों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर कॉलेज संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ. एचएस. त्रिपाठी,
रजिस्ट्रार, बीयू

Badri Gautam

तीन मई से शुरू की जाएगी प्रवेश प्रक्रिया

सिटी रिपोर्टर । आईएसआई कोलकाता ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में होने वाले प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 3 मई से होगी, जो 1 जून तक जारी रहेगी। 5 मई से लेकर 5 जून तक फीस भरी जा सकेगी। एडमिशन टेस्ट 11 जुलाई को होगा। बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स ,मैथमैटिक्स, मास्टर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, मैथमैटिक्स, साइंस इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स सहित अन्य कोर्स में प्रवेश मिलेगा। जानकारी के लिए www.isical.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।

सीएसआईआर देगा स्कूली बच्चों को इनोवेशन अवॉर्ड

CBSE UPDATE

सिटी रिपोर्टर . इंदौर

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) की ओर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के विद्यार्थियों के लिए इनोवेशन अवॉर्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर छिपा नवाचार और शोध के प्रति उनकी रुचि को बाहर लाना है। इसके लिए कक्षा 12वीं के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें साइंटिफिक व टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, डिजाइन, आइडिया और सॉल्यूशन के आधार पर विजेता चुने जाएंगे। इसके विजेता को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह उपविजेता को 50 हजार, तृतीय को 30 हजार, चौथे को 20 हजार और पांचवें स्थान पर आने वाले को 10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

Baori Gautam

नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर, बनेंगे नए पाठ्यक्रम

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति लागू करने की अनुशंसा कर दी। इसके क्रियान्वयन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अगले सत्र से नई नीति के तहत पाठ्यक्रमों को अपग्रेड कर नए पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड आफ स्टडीज को पाठ्यक्रमों की समीक्षा करना है, ताकि उनमें नए टापिक जोड़े जा सके। इसके लिए 23-24 अप्रैल को विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलवाई है, जिसमें बोर्ड आफ स्टडीज के चेयरमैन से नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों को अगले सत्र से पढ़ाया जा सकेगा।

कौशल विकास और इंडस्ट्री की जरूरत आधारित पाठ्यक्रम अब शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने यूजी-पीजी कोर्स में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस पर 28 विषयों की बोर्ड आफ स्टडीज ने काम शुरू कर दिया है, जिसमें मैनेजमेंट, साइंस, कामर्स, आर्ट्स, जर्नलिज्म,

पहल

- **23-24 अप्रैल को की जाएगी मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा**
- **गूगल मीट पर बोर्ड आफ स्टडीज के चेयरमैन देंगे सुझाव**

फैशन डिजाइनिंग सहित अन्य विषय शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पाठ्यक्रम में पुराने सिलेबस से जरूरी विषय छोड़कर बाकी टापिक हटाए जा रहे हैं। ऐसे विषय जोड़ रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों को खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में आसानी हो। पाठ्यक्रमों में संबंधित इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए टापिक रखे जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलाजी से रूबरू करवाया जा सके। पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए प्रदेशभर के सभी विश्वविद्यालय और कालेजों को सहयोग करने पर जोर दिया है। विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डा. धीरेंद्र शुक्ला ने बताया 23-24 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आनलाइन बैठक बुलवाई है।

Badri Gautam

कर्मचारियों को उपचार के लिए मिले चिकित्सा अग्रिम

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम देने की मांग कर्मचारी संघ ने की है। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य शासन के कर्मचारी एवं उनका परिवार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शासकीय अस्पतालों में बिस्तर न मिलने की स्थिति में कर्मचारी एवं उनका परिवार महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पतालों में पहले ही लाखों रुपये एडवांस के रूप में जमा करा लिए जाते हैं।

कर्मचारी के पास एक मुश्त इतनी बड़ी रकम न होने के कारण उन्हें बाजार से ब्याज पर पैसा उठाना पड़ जाता है, जो तत्काल पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। यद्यपि शासन के द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बाद कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। कोरोना के इस दौर में शासन यदि केंद्र की तर्ज पर चिकित्सा अग्रिम की राशि कर्मचारियों को बीमार पड़ते ही दे दी जाये तो कर्मचारियों को दर-दर भटकना नहीं पडेगा। संघ के योगेन्द्र दुबे,अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, मंसूर बेग, दुर्गेश पाण्डे, मुकेश धनगर, अजय सिंह ठाकुर, विजय गौतम, अतुल जोशी, राकेश सेंगर, नितिन अग्रवाल, राकेश उपाध्याय, तरूण पंचोली, मनीष चैबे, श्यामनारायण तिवारी, राकेश दुबे, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिख, अब्दुल्ला चिश्ती प्रणव साहू मनीष लोहिया, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला ने मुख्यमंत्री को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है कि कोविड महामारी के इस दौर में केंद्र शासन के समान राज्य कर्मचारियों को भी चिकित्सा अग्रिम सुविधा दी जाए।

1. कोरोना महामारी में राज्य शासन के कर्मचारी एवं उनका परिवार भी चपेट में
2. शासकीय अस्पतालों में बिस्तर नही, निजी अस्पतालों में जाने मजबूर
3. कर्मी के पास एकमुश्त पैसा न होने से ब्याज पर उठाना पड़ता है पैसा

Badri Gautam

आरोपियों की करतूतों की कुंडली पुलिस ने खंगाली

स्कूल कारोबार की आड़ में सरगना पार्टनरशिप में चलाता था सेक्स रैकेट

ग्वालियर. कलेक्टर दफ्तर के पास सेक्स कारोबार चलाने वाले तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी करतूतों की कुंडली सामने आ रही है। सेक्स के धंधे का सरगना अनुज शिवहरे गुरसरांय, झांसी का रहने वाला है। उसका असली धंधा शराब की तस्करी और सेक्स रेकेट चलाना है, लेकिन इन धंधों की कमाई को छिपाने के लिए उसने स्कूल खोल रखा है। उसकी आड़ में घिनौने कारोबार करता है। उसकी तलाश में पुलिस झांसी में उसके घर को भी खंगाल आई है। लेकिन सेक्स कारोबार के सरगना अनुज और उसके पार्टनर गौरव जैन का पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है कि दोनों पर इनाम की तैयारी की जा रही है। दिल्ली और कोलकाता की युवतियों को ठेके पर यहां लाकर उनसे सेक्स का धंधा करवाने वाला अनुज शिवहरे और उसका साथी गौरव जैन दोनों अंडरग्राउंड हैं। दोनों के मोबाइल भी उसी दिन से स्विच ऑफ हैं जब पुलिस ने उनके ठिकाने पर दबिश दी थी।